EDITOR'S SCATVIEW

Manoj Kumar Madhavan

The 'Make in India' policy is expected to get a boost with the ease of business and local cable manufacturing thrust that is being pushed by the Indian government. The directive by the government asking telecom companies to look at alternate routes for supply of 5G hardware is intended to target Chinese companies like Huawei & ZTE. This will provide the Indian telecom and cable equipment suppliers a chance to boost their manufacturing capacity. There are ample incentives being offered by the government to prospective Indian companies willing to invest in this.

This will take a few years to make an impact but definitely will propel Indian manufacturing sector to ramp up. The 'ease of business' will also encourage local and FDI to a great extent. I am very optimistic that the next decade is of India. There is bound to be a phenomenal transformation across the sectors.

Department of Telecommunications (DoT) last year had written a letter and requested TRAI to reconsider its recommendations on the Regulatory Framework for OTT communication services and suggest a suitable regulatory mechanism for OTTs, including issues relating to 'selective banning of OTT services' as part of its recommendations.

TRAI has said that a fresh consultation process may be initiated to frame suitable regulatory framework for OTT and is seeking inputs from stakeholders.

Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) has released a consultation paper on the regulatory mechanism for Over-The-Top (OTT) communication services, and selective banning of OTT Services.

Scatmag reports on the OTT regulations currently followed by various countries.

The Zee-Sony merger seems to be stuck in a legal maize with the battle now looking at ending up in the courts, after the SEBI ruling against the promoters of Zee holding any key position in any company, until the investigation is completed. The promoters should be entitled to the rule of natural justice and at the same time, the merger should go ahead without any hindrance with or without the Zee promoters.

(Manoj Kumar Madhavan)

भारत सरकार द्वारा व्यवसाय में आसानी और स्थानीय केबल विनिर्मा ण पर जोर दिये जाने से 'मेक इन इंडिया' नीति को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। सरकार द्वारा दूरसंचार कंपनियों को 5जी हार्डवेयर की आपूर्ति के लिए वैकल्पिक मार्गों पर विचार करने के निर्देश का उद्देश्य 'हुआवेई' और 'जेडटीई' जैसी चीनी कंपनियों को लक्षित करना है। इससे भारतीय दूरसंचार और केबल उपकरण आपूर्तिकर्ताओं को अपनी विनिर्माण क्षमता को बढ़ाने का मौका मिलना चाहिए। इसमें निवेश करने को ईच्छुक संभावित भारतीय कंपनियों को सरकार द्वारा पर्याप्त प्रोत्साहन की पेशकश की जा रही है।

इसका प्रभाव पड़ने में कुछ साल लगेंगे, लेकिन निश्चित रूप से यह भारतीय विनिर्माण क्षेत्र को बड़े पैमाने पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। व्यापार में आसानी से स्थानीय और एफडीआई को भी काफी हद तक बढ़ावा मिलेगा। मैं बहुत आशावादी हूं कि अगला दशक भारत का है। सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व परिवर्तन होना निश्चित है।

दूरसंचार विभाग (डॉट) ने पिछले साल एक पत्र लिखकर ट्राई से ओटीटी संचार सेवाओं के लिए नियामक ढ़ांचे पर अपनी सिफारिशों पर पुर्नविचार करने और ओटीटी के लिए एक उपयुक्त नियामक तंत्र का सुझाव देने का अनुरोध किया था, जिसमें इसकी सिफारिशों के हिस्से के रूप में ओटीटी सेवाओं पर चयनात्मक प्रतिबंध से संबंधित मुद्दे भी शामिल होंगे।

ट्राई ने कहा कि ओटीटी के लिए उपयुक्त नियामक ढ़ांचा तैयार करने के लिए एक नयी परामर्श प्रक्रिया शुरू की जा सकती है और वह हितधारकों से इनपुट मांग रहा है।

भारतीय दूरसंचार नियामक प्रधिकरण (ट्राई) ने ओवर-द-टॉप (ओटीटी) संचार सेवाओं के लिए नियामक तंत्र और ओटीटी सेवाओं पर चुनिंदा प्रतिबंध लगाने पर एक परामर्शपत्र जारी किया है।

वर्तमान में विभिन्न देशों द्वारा अपनाये जा रहे ओटीटी नियमों पर स्कैटमैग रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा है।

जी-सोनी का विलय कानूनी पचड़े में फंसता दिख रहा है और सेबी के फैसले के बाद अब यह लड़ाई अदालतों में जाकर खत्म होती दिख रही है, जब तक कि जांच पूरी नहीं हो जाती है, जी के प्रमोटरों के किसी भी कंपनी में कोई भी महत्वपूर्ण पद संभालने पर रोक लगा दी गयी है। प्रवर्त कों को प्राकृतिक न्याय के नियम का अधिकार होना चाहिए और साथ ही जी प्रवर्तकों के साथ या उनके बिना भी विलय बिना किसी बाधा के आगे बढ़ना चाहिए।

(Manoj Kumar Madhavan)